Ojaank Gurukul | IAS

डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व: अमेरिकी मौद्रिक नीति पर संघर्ष

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक नई जंग छेड़ दी है, और इस बार उनका निशाना है अमेरिका का सेंट्रल बैंक – फेडरल रिजर्व। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, जिसके वर्तमान चेयरमैन जेरोम पॉवेल हैं।

ट्रंप ने पॉवेल पर ब्याज दरों को कम न करने का आरोप लगाया है। अमेरिका में ब्याज दरों में थोड़ा भी बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। आइए समझते हैं कि यह विवाद क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

by OJAANK IAS

Ojaank Gurukul | IAS

अमेरिकी फेडरल रिजर्व और ब्याज दरों का मुद्दा

वर्तमान स्थिति

फेडरल रिजर्व ने वर्तमान में ब्याज दरें 4.25% से 4.5% के बीच रखी हैं। यह भारत के रेपो रेट की तरह है, जो हाल ही में 6.5% से घटाकर 6% किया गया है।

ट्रंप का पक्ष

ट्रंप चाहते हैं कि ब्याज दरें और कम की जाएँ। उनका तर्क है कि उनकी टैरिफ नीतियों से अमेरिका को अधिक राजस्व मिलेगा और विदेशी प्रतिस्पर्धा कम होगी।

फेडरल रिजर्व का पक्ष

फेडरल रिजर्व का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियाँ मुद्रास्फीति बढ़ाएँगी। अगर ब्याज दरें कम की गईं, तो अर्थव्यवस्था अत्यधिक गरम हो जाएगी।

ट्रंप और पॉवेल के बीच तनाव

सीधा आरोप

ट्रंप ने पॉवेल पर सीधा आरोप लगाया है कि वह "बहुत देर से और गलत" मौद्रिक नीति अपना रहे हैं। यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

संवैधानिक बहस

ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि वे पॉवेल को हटा सकते हैं, जिससे अमेरिका में संवैधानिक बहस छिड़ गई है कि क्या राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र एजेंसी के प्रमुख को हटाने की शक्ति है।

नया चेयरमैन

ट्रंप चाहते हैं कि केविन वॉश को फेड का चेयरमैन बनाया जाए, जो पहले भी फेडरल रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं और ब्याज दरें कम रखने के पक्षधर हैं।

फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता का मुद्दा

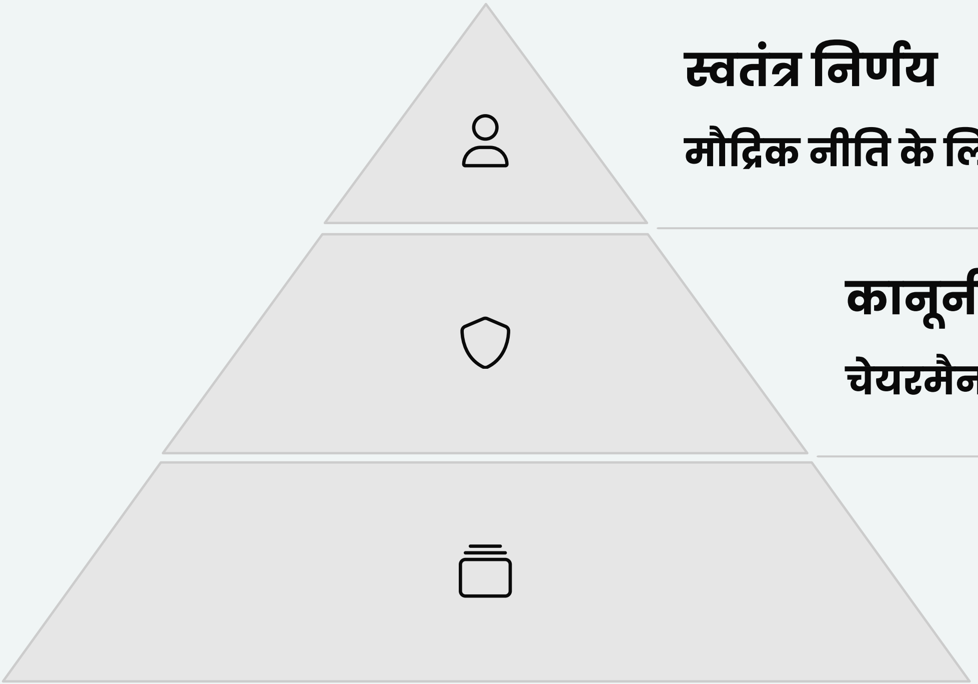

स्वतंत्र निर्णय

मौद्रिक नीति के लिए स्वतंत्र निर्णय आवश्यक

कानूनी संरक्षण

चेयरमैन को 4 साल का निश्चित कार्यकाल

ऐतिहासिक परंपरा

अब तक किसी राष्ट्रपति ने फेड चेयर को नहीं हटाया

फेडरल रिजर्व के चेयर को 4 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और उन्हें केवल किसी विशेष कारण से ही हटाया जा सकता है। यह कानूनी संरक्षण उन्हें राजनीतिक दबाव से बचाता है। मजेदार बात यह है कि 2018 में ट्रंप ने ही पॉवेल को नामित किया था, और 2022 में बाइडन ने उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया।

संवैधानिक विवाद और सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में मामला

क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र एजेंसियों को प्रभावित कर सकते हैं?

महत्वपूर्ण निर्णय

निर्णय तय करेगा क्या ट्रंप पॉवेल को हटा सकते हैं

व्यापक प्रभाव

निर्णय का दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों पर असर होगा

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (SCOTUS) में इस समय एक महत्वपूर्ण मामला चल रहा है जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र एजेंसियों को प्रभावित करने की शक्ति है। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होगा कि क्या ट्रंप पॉवेल को हटा सकते हैं या नहीं। इस निर्णय का प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों पर पड़ेगा।

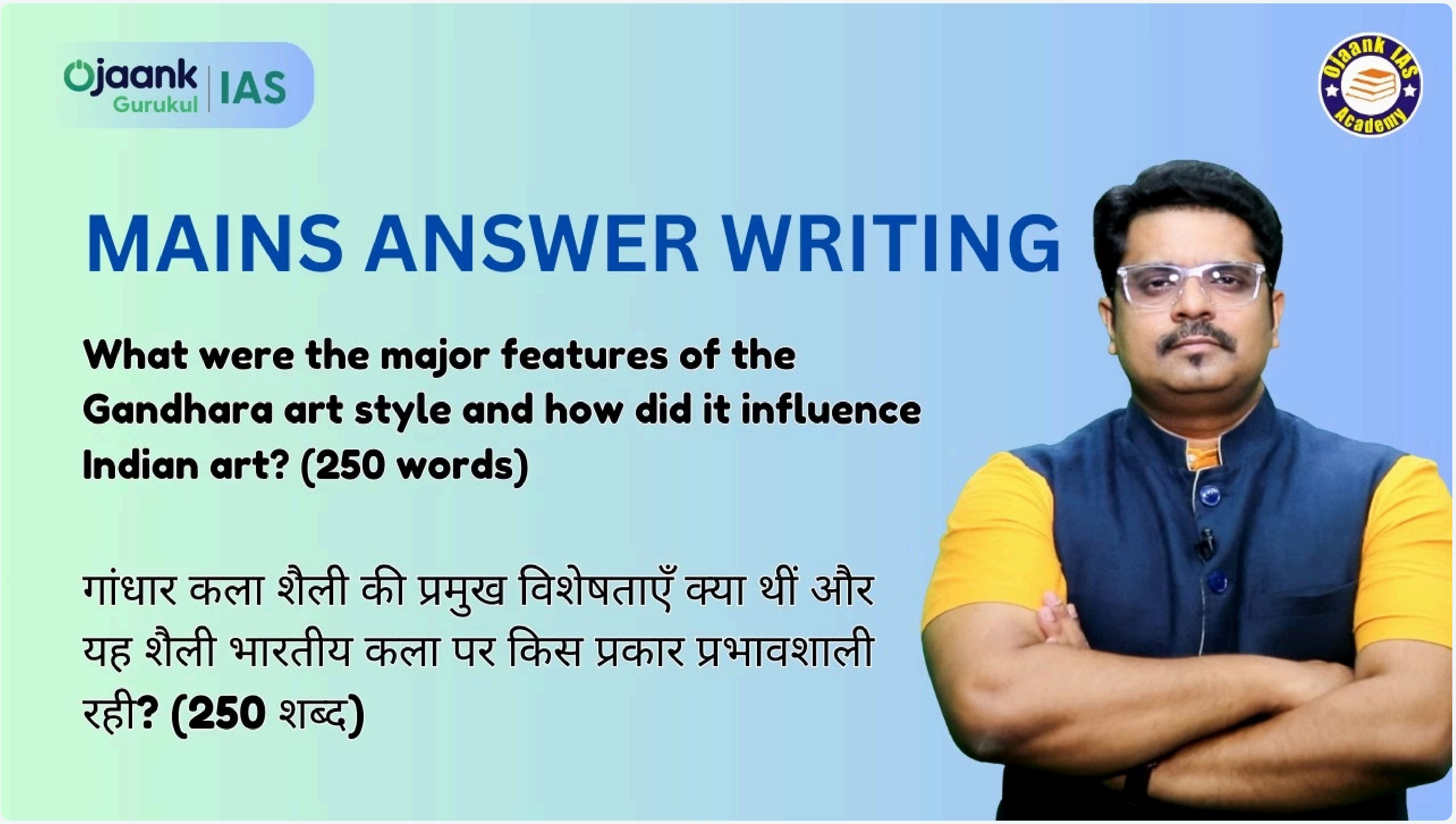

✍🏻 150–250 words | Think like a Civil Servant

CLICK TO JOIN 👇🏻

https://www.ojaank.com/blog/detail/examine-the-challenges-posed-by-uneven-demographic-changes-to-the-principle-of-proportional-representation-in-the-lok-sabha.-should-india-continue-periodic-delimitation-or-freeze-seat-allocation-assess-from-constitutional-and-political-perspectives

📞 **For more information, call us: 8750711100/22/33/44/55, or WhatsApp us:- 8285894079**

💪🏻 **Daily practice = Sure success**

आर्थिक प्रभाव और बाजार की प्रतिक्रिया

स्टॉक मार्केट अस्थिरता

फेड की स्वतंत्रता पर संदेह से बाजार में अस्थिरता

निवेशक विश्वास कम

अमेरिकी संस्थानों पर विश्वास घटेगा

वैश्विक प्रभाव

वैश्विक पूंजी प्रवाह और डॉलर की मजबूती प्रभावित होगी

मुद्रास्फीति की आशंका

लंबी अवधि की मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़ेंगी

फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर संदेह से स्टॉक मार्केट में अस्थिरता आ सकती है। बाजार फेड की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान देता है। अगर लोगों को लगेगा कि फेडरल रिजर्व स्वतंत्र नहीं है, तो वे स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, जिससे बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में अस्थिरता आएगी।

ट्रंप का राजनीतिक उद्देश्य

अल्पकालिक आर्थिक विस्तार

ट्रंप चाहते हैं कि अल्पकालिक आर्थिक विस्तार हो ताकि वे लोगों को दिखा सकें कि उनके राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की जीडीपी बढ़ गई है।

मध्यावधि चुनाव

अगले साल अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि उनकी पार्टी को इसमें लाभ मिले।

स्टॉक मार्केट और रोजगार आंकड़े

ट्रंप स्टॉक मार्केट और रोजगार आंकड़ों में सुधार दिखाना चाहते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़े।

भारत पर संभावित प्रभाव

विदेशी निवेश में वृद्धि

अमेरिका में ब्याज दरें कम होने से भारत जैसे विकासशील देशों में निवेश बढ़ सकता है, जिससे FII और FDI प्रवाह में वृद्धि होगी।

रुपये का मूल्यवर्धन

अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से रुपया मजबूत हो सकता है, जिससे भारत का आयात सस्ता हो सकता है, विशेष रूप से सोना और तेल।

भारतीय कंपनियों के लिए लाभ

भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी देशों में उधार लेने की लागत कम हो सकती है, जिससे उनके व्यापार में विस्तार हो सकता है।

भारतीय मौद्रिक नीति पर प्रभाव

आरबीआई के पास भी ब्याज दरें कम करने का अधिक अवसर होगा, जो वर्तमान में 6% पर हैं।

केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता का महत्व

1

ऐतिहासिक परंपरा

अमेरिका में कई दशकों से मौद्रिक नीति स्वतंत्र रही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

2

भारत में भी बहस

भारत में भी उर्जित पटेल और रघुराम राजन के समय में आरबीआई की स्वतंत्रता पर बहस हुई थी।

3

संस्थागत अखंडता

संस्थागत अखंडता आर्थिक स्थिरता और विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4

वैश्विक प्रभाव

अमेरिका में फेड की स्वतंत्रता का प्रभाव दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों पर पड़ता है।

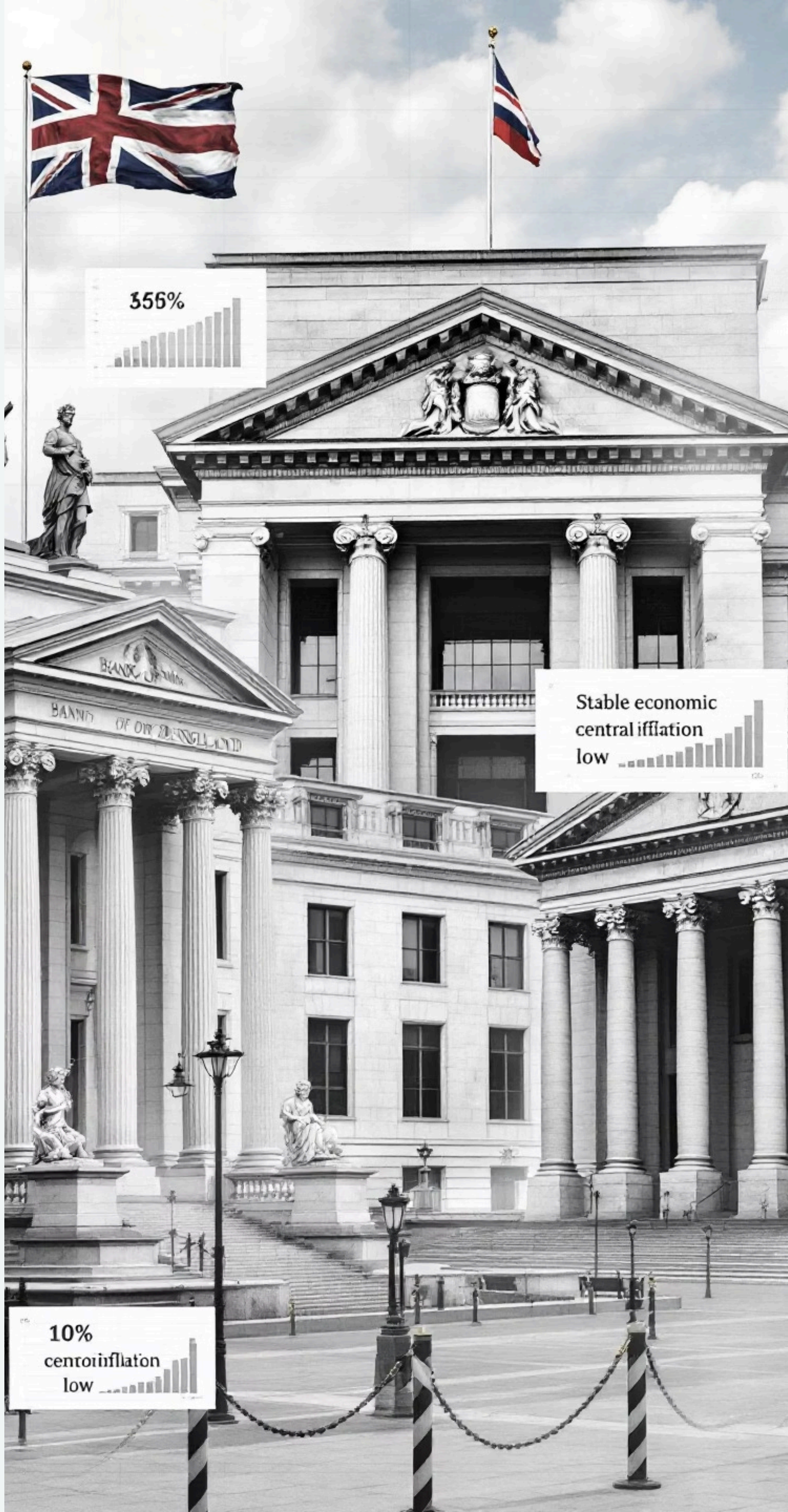

निष्कर्ष: मौद्रिक नीति और राजनीतिक हस्तक्षेप

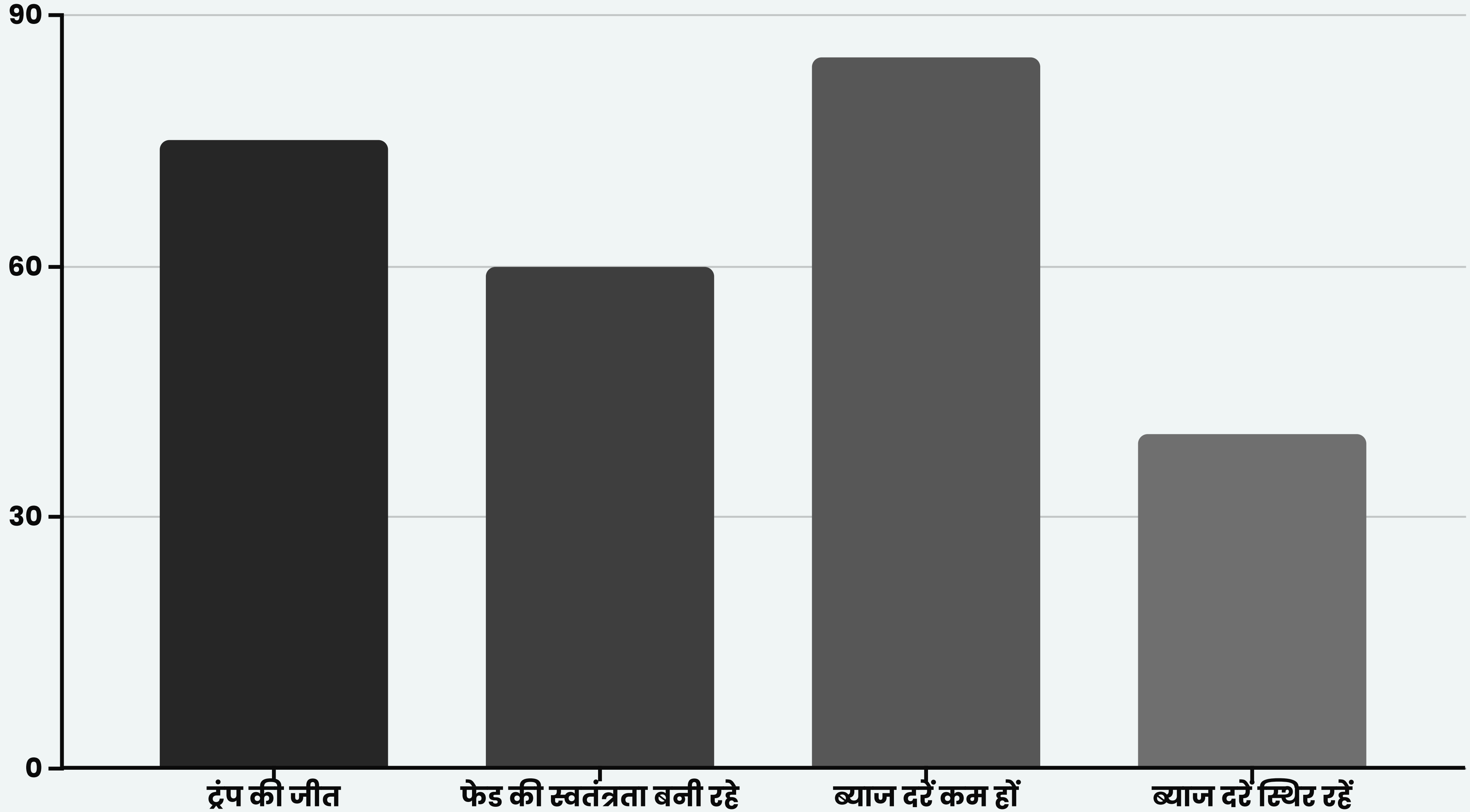

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच चल रहा संघर्ष न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ट्रंप अपने एजेंडे में सफल होते हैं और अमेरिका ब्याज दरें कम करता है, तो इससे भारत को लाभ हो सकता है। लेकिन केंद्रीय बैंकों की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठने से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

Fill This Form and Apply Now 👇🏻👇🏻👇🏻

https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit